

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 563वीं बैठक दिनांक 04/04/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8145/2021 M/s Vijay & Company, Raj Bhawan, Katni Road, PO - Maihar, Dist. Satna, MP - 485771 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.679 ha. (71250 tonne per annum) (Khasra No. 903/2), Village - Bathia, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) EIA Consultant M/s. P&M Solutions, NOIDA, (U.P.).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 903/2), Village - Bathia, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 3.659 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 480वीं दिनांक 13/02/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर आबादी है । खदान के उत्तर दिशा से होकर एच.टी. लाईन गुजर रही है जिसके दोनों ओर 50-50 मीटर का

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

सेट-बैक छोड़ा जाना होगा तत्संदर्भ में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए । खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 160 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि खनन क्षेत्र में 02 पेड़ आम के लगे हुए हैं, जिन्हें नहीं काटा जावेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे शिक्षा सुविधायें, विद्यालय की मरम्मत, खेलकूद सामग्री, पेयजल की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जहाँ तक संभव होगा उत्खनन में रॉक ब्रेकर का उपयोग तथा जहाँ आवश्यक होगा माइल्ड ब्लास्टिंग की जावेगी । परियोजना प्रस्तावक ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि खनन क्षेत्र में 810 पेड़, आवागमन के रास्ते में 2500 पेड़ तथा पंचायत एवं स्कूल इत्यादि में 2210 पेड़ लगाने की योजना है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ खदान के उत्तर दिशा से होकर एच.टी. लाईन गुजर रही है जिसके दोनों ओर 50-50 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना तथा वचन पत्र कि वृक्षारोपण प्रथम 02 वर्ष पूर्ण कर लिया जावेगा ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी व सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ परिवहन मार्ग को गूगल मैप पर दर्शाते हुए प्रस्तुत करें ।
- ✓ शारदा देवी की पहाड़ी पर 1500 पेड़ वन विभाग के द्वारा लगवाये जाने का शपथ पत्र ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -71250 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.75 लाख एवं रिकरिंग 04.55 लाख प्रति वर्ष
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.1.50 लाख :-

S. No	Activities	Deliverable	Rate	Total cost (Rs.)
1	Infrastructure Development			
	Distribution of sport kits to the students in the school of Bathiya village	1 school	-	20,000

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

	Repair of ground wall/roof top of the school in village Bhatiya	1 school	@ Rs. 20,000	20,000
	Financial aid to Anganwadi for the programme "Poshan Aahar" .		@ Rs. 50,000	50,000
	Installation of hand pump in consultation with panchayat in Bathiya village with recharging pit. drinking water supply during summer season.	1 hand pump		45,000
2	Sustainable Livelihood			
	Provide employment to the local villagers 20 persons (direct) & 50 indirect. The payment to the workers will be done as per the Minimum Wages Act into the bank accounts preferably.	20	Wages will be given as per administrative rules.	
3	Health			
	Distribution of as sanitization kit (hand sanitizer, hand gloves and nose mask) and training to villagers for precautions needed in pandemic in village Bhatiya	50 person	@ Rs. 100/set including gloves, sanitizer & mask	5000
	Heath checkup camps	1 health camp	Rs 10,000/ camp	10,000
	Total CER budget			1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5520 पौधों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जावेगा :-

- A. **Plantation in Barrier Zone (7.5 mtr from the quarry lease area and 50m from the Power line over 1.20 Ha area)**

Name	Number in barrier zone
Mango	150
Neem	150
Khamer	100
Shisham	200
Chirol	200
Karanj	200
Sitafal	150

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

Kumbhi	200
Total	1450

B. Plantation along the Transportation route (of minimum 01 meter height)

Name	Number along the transport route
Neem	100
Pipal	100
Khamer	100
Shisham	100
Mahua	50
Amaltas	100
Sissoo	50
Sehtoot	100
Jamun	100
Karanj	100
Putranjiva	50
Maulshree	50
Kadam	100
Arjun	100
Total	1200

C. The PP will provide fund for plantation and maintenance 1500 saplings to Local Forest Protection Committee, Sharda Devi Pahadi temple Sharda Devi Pahadi temple in the coming monsoon season of 2022.

Neem	600
Bargad	300
Peepal	300
Bel	300
Total	1500

D. 1370 saplings will be provided to Gram Panchayat. The species will be as per the demand and mainly fruit growing trees.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

2. Case No 8144/2021 M/s Rai Stone Crusher, Prop., Shri Amit Kumar Rai, Rai Bhawan, Katni Road, PO - Maihar, Dist. Satna, MP – 485771 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.659 ha. (71250 tonne per annum) (Khasra No. 903/4), Village - Bathia, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) EIA Consultant M/s. P&M Solutions, NOIDA, (U.P.).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 903/4), Village - Bathia, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 3.659 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 480वीं दिनांक 13/02/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पश्चिम दिशा में आबादी है जो 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । खदान के उत्तर दिशा से होकर एच.टी. लाईन गुजर रही है जिसके दोनों ओर 50-50 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा तत्संदर्भ में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जहाँ तक संभव होगा खनन कार्य में रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जावेगा तथा जहाँ आवश्यक होगा, माइल्ड ब्लास्टिंग की जावेगी । खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 195 मीटर रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान धूल की समस्या तथा सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि खनन क्षेत्र में 780 पेड़, आवागमन के रास्ते में 2500 पेड़ तथा पंचायत एवं स्कूल इत्यादि में 2210 पेड़ लगाने की योजना है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि इस खदान से धूल की समस्या न हो । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ खदान के उत्तर दिशा से होकर एच.टी. लाईन गुजर रही है जिसके दोनों ओर 50-50 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना होगा तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना तथा वचन पत्र कि वृक्षारोपण प्रथम 02 वर्ष पूर्ण कर लिया जावेगा ।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ परिवहन मार्ग को गूगल मैप पर दर्शाते हुए प्रस्तुत करें ।
- ✓ शारदा देवी की पहाड़ी पर 1500 पेड़ वन विभाग के द्वारा लगवाये जाने का शपथ पत्र ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन 71,250 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 16.75 लाख एवं रिक्रिंग 0.85 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख :-

S. No	Activities	Deliverable	Rate	Total cost (Rs.)
1	Infrastructure Development			
	Financial aid to Anganwadi for the programme "Poshan Aahar".		@ Rs. 50,000	65,000
	Installation of hand pump in consultation with panchayat in Bathiya village with recharging pit. drinking water supply during summer season.	1 hand pump		60,000
2	Sustainable Livelihood			
	Provide employment to the local villagers 20 persons (direct) & 50 indirect. The payment to the workers will be done as per the Minimum Wages Act into the bank accounts preferably.	20	Wages will be given as per administrative rules.	
3	Health			
	Health Check up camp	1 health camp	Rs 25,000/ camp	25000
	Total CER budget			1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5490 पौधों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जावेगा :-

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

A. Plantation in Barrier Zone (7.5 mtr from the quarry lease area and 50m from the Power line over 0.83 Ha area

Name	Number in barrier zone
Mango	200
Neem	100
Khamer	100
Shisham	100
Chirol	100
Karanj	100
Sitafal	100
Kumbhi	100
Total	1000

B. Plantation along the Transportation route(of minimum 01 meter height)

Name	Number along the transport route
Neem	100
Pipal	100
Khamer	100
Shisham	50
Mahua	50
Amaltas	50
Sissoo	100
Sehtoot	100
Jamun	100
Karanj	50
Putranjiva	50
Maulshree	50
Kadam	50
Arjun	50
Total	1000

C. The PP will provide fund for plantation and maintenace 1500 saplings to Local Forest Protection Committee, Sharda Devi Pahadi temple Sharda Devi Pahadi temple in the coming monsoon season of 2022.

Neem	600
Bargad	300
Peepal	300
Bel	300
Total	1500

D 1990 saplings will be provided to Gram Panchayat. The species will be as per the demand and mainly fruit growing trees.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- 3. Case No 7322/2020 Smt. Manju Singh W/o Shri Narendra Bahadur Singh, R/o Bamhangawan, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna Prior Environment Clearance for Laterite Quarry in an area of 5.70 ha. (18530 cum per annum) (Khasra No. 2P), Village - Bihra, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) EIA Consultant Globus Environment Engineering Service, Lucknow (U.P.)**

This is case of Laterite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2P), Village - Bihra, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) 5.70 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 448वीं दिनांक 23/07/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण समिति की आज दिनांक 04/04/22, 563वीं बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

- 4. Case No 8349/2021 M/s. Sun Stone, Partner Shri Dhanjay Khandelwal, R/o, Paras Jewelars, Sardar Bazar, Murar, Dist. Gwalior, MP, 9826785005 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.860 ha. (150000 cum per annum) (Khasra No. 1051/2, 1053, 1056, 1981, 1982), Village - Dirman & Pali Dirman, Tehsil - Gohad, Dist. Bhind (MP) Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1051/2, 1053, 1056, 1981, 1982), Village - Dirman & Pali Dirman, Tehsil - Gohad, Dist. Bhind (MP) 3.860 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 494वीं दिनांक 31/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्व दिशा में 195 मीटर पर नहर तथा उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर पश्चिम दिशा में 406 मीटर पर पक्का रोड़ है। खदान की पश्चिम दिशा में 270 मीटर पर एक शेड है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 470 मीटर पर प्राकृतिक नाला है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान रोड़ में सुधार व सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे पेयजल की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये तथा खनिज का परिवहन 40 मै.टन क्षमता के वाहन से किया जाये, प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आ सके व इस खदान से धूल की समस्या न हो। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित फार्म-2।
- ✓ जन सुनवाई के पूर्ण कार्यवाही की प्रति।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना तथा वचन पत्र कि वृक्षारोपण प्रथम 02 वर्ष पूर्ण कर लिया जावेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।
- ✓ भू- जल विश्लेषण रिपोर्ट में टी.एस.एस. एवं फ्लोराईड वैल्यू के बारे में स्पष्टीकरण।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -1,50,000 मी.³ प्रति।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.80 लाख एवं रिकरिंग 03.37 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.50 लाख :-

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	वार्षिक आवर्ती व्यय रु.
1.	दिरमन गांव में रोड़ की मरम्मत की जाएगी	2,00,000
2.	ग्राम दिरमन में पीने के पानी के लिए बोरवैल खुदवाकर लिफ्टिंग पम्प लगाया जायेगा और उसे ओवरहेड टैंक में पाइपलाइन से जोड़ा जायेगा।	1,75,000

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

3.	ग्राम दिरमन में मुख की स्वच्छता, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिए जागरूकता शिविर।	20,000
4.	ग्रामीणों को सोलर कुकर उपलब्ध कराना। (रु 500 ग 110 परिवार)	55,000
कुल योग		4,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4632 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में तीन लाइनों में किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सो आदि।	1000
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1000 मी) के दोनों ओर (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, अशोक आदि	500
3	ग्राम पाली में तालाब के आस-पास वृक्षारोपण	अर्जून, महुआ, पीपल, नीम	200
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	2950
Total			4632

- 5. Case No 9085/2022 M/s Adavita Developers and Promoters Pvt. Ltd, K-6, First Floor, Khandelwal Complex, Opp. UBI Near Guljar Hotel, Madan Mahal, Dist, Jabalpur, MP . Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Shree Ram Heights" (Total Plot Area = 22271 sqm, Total Built-up Area = 66058.54) at Village - Zone-I Garha, Colony Sagda Tripuri, Tehsil & Dist. Jabalpur, MP. Env. Consult.:- M/s. Ambiantal Global Private limited. (Violation TOR).**

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Shree Ram Heights" (Total Plot Area = 22271 sqm, Total Built-up Area = 66058.54) at Village - Zone-I Garha, Colony Sagda Tripuri, Tehsil & Dist. Jabalpur, MP.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

The case was presented by the PP and their Env. Consultant Env. Consult. Shri Sandhu M/s. Ambiantal Global Private limited in the, wherein it was observed that this is a violation project and construction of few blocks have been completed. PP submitted following details of the project:

- M/s Adavita Developers and promoters Pvt. Ltd. has proposed the Group Housing Project “ Shree Ram Heights” Khasra No. 150/2,150/1, 151,152/1,154/2, 153,152/2 Zone-1(Garha), Colony :- Sagda Tripuri, Jabalpur, Madhya Pradesh.
- The Proposed estimated built-up area of 22271.00 m² . Total built up Area is 66,058.54m² As per the EIA Notification and its amendment, the project is falling in the category 8 (b).
- Group housing project will provide good infrastructure facilities and state of the art technology and will be developed taking into account eco friendly features in order to provide a healthier environment
- The proposed site has been earmarked for residential purpose as per master plan of Jabalpur -2021. Therefore no permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan) will occur.

During presentation it was observed by committee through Google image as per the co-ordinates provided by that prior to the construction of project as per previous Google image of 03/2013 some trees (approx. 15) were in existance on the project site and all have been uprooted in the previous image of 12/2013 and area has been cleared. Committee during presentation asked PP whether for trees uprooting approval of competent authrotiy was obtained or not and what was the land use at that time for which PP & consultant were unaware and seeked time to answer the reply and requested that they may be given some time to address this query. Committee after deliberation decided that PP shall collect all the relevant information within a week time and this case shall be listed in the next SEAC meeting scheduled in the first week of Arril, 2022.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Shree Ram Heights" (Total Plot Area = 22271 sqm, Total Built-up Area = 66058.54) at Village - Zone-I Garha, Colony Sagda Tripuri, Tehsil & Dist. Jabalpur, MP.

The case was presented by the PP and their Env. Consultant Env. Consult. Shri Sandhu M/s. Ambiantal Global Private limited in the, wherein it was observed that this is a violation project and construction of few blocks have been completed. PP submitted following details of the project:

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- M/s Adavita Developers and promoters Pvt. Ltd. has proposed the Group Housing Project “ Shree Ram Heights” Khasra No. 150/2,150/1, 151,152/1,154/2, 153,152/2 Zone-1(Garha), Colony :- Sagda Tripuri, Jabalpur, Madhya Pradesh.
- The Proposed estimated built-up area of 22271.00 m² . Total built up Area is 66,058.54m² As per the EIA Notification and its amendment, the project is falling in the category 8 (b).
- Group housing project will provide good infrastructure facilities and state of the art technology and will be developed taking into account eco friendly features in order to provide a healthier environment
- The proposed site has been earmarked for residential purpose as per master plan of Jabalpur -2021. Therefore no permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan) will occur.

During presentation it was observed by committee through Google image as per the co-ordinates provided by that prior to the construction of project as per previous Google image of 03/2013 some trees (approx. 15) were in existence on the project site and all have been uprooted in the previous image of 12/2013 and area has been cleared. Committee during presentation asked PP whether for trees uprooting approval of competent authority was obtained or not and what was the land use at that time for which PP & consultant were unaware and sought time to answer the reply and requested that they may be given some time to address this query. Committee after deliberation decided that PP shall collect all the relevant information within a week time and this case shall be listed in the next SEAC meeting scheduled in the first week of April, 2022.

The case was presented by the PP and their Env. Consultant Shri Sandhu from M/s. Ambiantal Global Private limited. In spite of constant efforts PP could not connect online. During appraising of the on line available documents it was observed by the Committee that PP has properly furnished the information desired for the project appraisal. Several ambiguities / difference in information were observed by committee in the executive summary, form-1 and other documents filed by PP for project appraisal. Even PP is not sure of the category in which this case shall be appraised as has applied for both cat 8(b) in executive summary and cat 8(a) in Appendix-I. Similarly the built up area as per executive summary is 22271 sq meter while in Appendix-I it is mentioned as 66058.54 sq meter. The details of proposed DG sets are differently mentioned in executive summary and Appendix-I. The environmental sensitivity is also not addressed properly for point number 02, 07 & 08. The environmental consultant could not justify for these ambiguities and proposed to revise the entire set of documents. The committee

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

after deliberations recommends that PP may revise all the documents and provide relevant information which shall be similar in all documents such as executive summary, Appendix-I & conceptual plan etc with the copy of permission obtained by him for uprooting trees which were in existence before construction begins through SEIAA. Committee recommends that on above grounds this application may be rejected and PP may be asked to apply a fresh and case file may be sent to SEIAA for onward necessary action.

6. Case No 9086/2022 M/s Adani Logistic Ltd, Shri Dipesh Gandhi, Associate Vice President, Adani Corporate House, Shantigram Near Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad, Guj. - 382421 Prior Environment Clearance for Construction of Warehouse at Village - Bhenslay, Tehsil - Mhow, Dist. Indore, MP.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Warehouse at Village - Bhenslay, Tehsil - Mhow, Dist. Indore, MP.

Executive Summary of the project:

Adani Logistics Ltd. have proposed to develop Warehouse/Logistic Park at Village Bhenslay, Tehsil- Mhow, District- Indore, Madhya Pradesh on a land measuring 53,774 m². The geographical co-ordinates of project site are 22°37'12.90"N and 75°43'58.07"E. The proposed Warehouse buildings will be leased out to various clients who undertakes activities viz: Light & Heavy Engineering, Assembling, Manufacturing & Storage of Agro and non-agro products related to food & beverage industry, Textile products, Apparel, Leather and related products Tobacco products, Furniture, fittings & Artifact Products, Glass and related products; Wood and products of wood and cork including furniture, articles of straw and plated materials, Paper and paper products, Printing and reproduction of recorded media, Paints and chemicals within threshold limits, FMCG, Pharmaceuticals, Medicinal, Chemical and Botanical products, Rubber, Plastics and allied products, other non-metallic products, Basic metals, Fabricated metal products, including machinery and equipment, Computer, Electronic and optical products, Electrical equipment's and Electronic products, Industrial machinery and equipments; Automobiles products, Ancillaries and allied products; Defense & Aerospace Industries, Construction equipment and materials.

- The project site is well connected with Rau – Pitampur road. National Highway- 52 is 0.4 km towards S to the project site, NH-47 is approx. 6.5 km towards NNW and SH-1 is approx. 10.3 km towards S. The nearest railway station is Tihi

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

Railway Station which is approx. 20 m away from site boundary. Devi Ahilyabai Holkar Airport – 11.0 km (NE) direction of the project site.

- The total water requirement will be approx. 98 KLD out of which domestic water requirement is 45 KLD. The freshwater demand will be approx. 30 KLD. The source of water supply will be groundwater for which CGWA process is under progress. It is expected that the project will generate approx. 39 KLD of wastewater. The wastewater will be treated in onsite STP of 50 KLD capacity. STP will be installed in phases as per the occupancy of project. The treated effluent will be reused for flushing, & horticulture. The balance water requirement for horticulture will be met from STP treated water sourced from external agency.
- Total runoff load is 1251.73 m³/hr considering roof-top area, green area & paved area. Total of 8 Rainwater Harvesting pits are proposed for artificial ground water recharge.
- The power shall be supplied by State Electricity Board. The total demand load for the Warehouse Project will be approx. 440 KW. There is provision of 125 kVA capacity DG set for power back up.
- Adequate provision will be made for the heavy vehicle parking at the project site to allow smooth movement. Total 592 nos. of parking including 319 (Car) + 250 (2-Wheeler) + 23 (Truck) are proposed. For smooth movement of traffic internal roads of 9.0 m and 6.0 m (peripheral) are proposed.
- During the operation phase, solid waste generated from the project shall be approx. 309 kg per day. Solid waste management during the operation stage shall be carried out through Organic Waste Converter (OWC) for the biodegradable waste and government approved vendors for the dry waste.
- Total green area measures 17745.5sqm i.e. 33% of the plot area. Native species will be planted inside the premises.
- Total amount of the soil excavated for construction is 33000 cum and filling quantity is 42000 cum. The excavated soil will be used in backfilling and other area development activities.
- Effective measures will be incorporated to minimize the energy consumption.
- The proposed project will bring employment opportunity during construction and operation phase both in terms of direct and indirect employment. There will be

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

economic impact in terms of generating opportunities for secondary occupation within and around the complex.

- The total Cost (Land + Development) of the proposed project will be INR 101.67 Crore.
- No court matters/orders of the court pertaining to the project.

The case was presented by the PP Shri and their Env. Consul Dr. Dhiraj Kumar Singh M/s. Grass Roots Research & Creation India (P) Ltd., Ghaziabad, U.P. with the salient features of the project, and other details of the project, which reveals following:-

- Adani Logistics Limited have proposed to develop Warehouse/Logistic Park at Village – Bhenslay, Tehsil – Mhow, District – Indore, Madhya Pradesh .
- Survey Nos. - 36/min-1(S), 37/1(S), 37/2(S), 38/1(S), 55/1(S), 55/2/min-1(S), 55/5/2/min-1/2(S), 55/3/min-1(S), 55/4/min-1(S), 55/5/1(S), 55/5/2/min-1/1(S) .
- Plot Area – 53,774 sqm with built up area – 32,566. 97 sqm
- Project activity is covered under item 8(a) of SCHEDULE of EIA Notification, 2006 and is categorized as Category ‘B2’ since the built-up area is between 20,000 sqm to 1,50,000 sqm.
- The proposed Warehouse/logistic park buildings will be leased out to various clients who undertakes activities viz:
- Light & Heavy Engineering, Assembling, Manufacturing & Storage of Agro and non-agro products related to food & beverage industry, Textile products, Apparel, Leather and related products Tobacco products, Furniture, fittings & Artifact Products, Glass and related products; Wood and products of wood and cork including furniture, articles of straw and plated materials, Paper and paper products, Printing and reproduction of recorded media, Paints and chemicals within threshold limits, FMCG, Pharmaceuticals, Medicinal, Chemical and Botanical products, Rubber, Plastics and allied products, other non-metallic products, Basic metals, Fabricated metal products, including machinery and equipment, Computer, Electronic and optical products, Electrical equipment’s and Electronic products, Industrial machinery and equipments; Automobiles products, Ancillaries and allied products; Defense & Aerospace Industries, Construction equipment and materials.
- **Highlights of the Project**

Area Statement	Details
----------------	---------

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

Land Area (@100%)	53774 sqm
Permissible Ground Coverage (@60% of plot area)	32264.4 sqm
Proposed Ground Coverage (@52.26% of plot area)	28105.47 sqm
Permissible FAR (@1 of plot area)	53774 sqm
Total Built-up area	32566.97 sqm
Building Shed Height	15 m
Green Area	17745.5 sqm (33% of total plot area)

- The land where the proposed buildings are proposed is not flat in nature with level difference of ~ 1.0 meters
- Project will not intersect any natural drainage route
- Well planned storm water drainage will be designed for internal storm water drainage.
- No impact on the natural drainage system is anticipated.
- Earthwork including soil excavation and cutting of the earth will have to be moved
- Total amount of the soil excavated for construction is 33000 cum and filling quantity is 42000 cum. The excavated soil will be used in backfilling and other area development activities.
- During the operation phase, solid waste generated from the project shall be ~309 kg per day .
- Solid Waste Management shall be carried out as per Solid Waste Management Rules, 2016.
- During the operation phase, solid waste generated from the project shall be ~309 kg per day
- Solid Waste Management shall be carried out as per Solid Waste Management Rules, 2016.
 - Effective measures have been incorporated to minimize the energy consumption in following manners:
 - All internal and external lighting shall be BEE star rated.
 - All common spaces including streetlights (where there is no use of light for reading purposes), shall be of “LED”.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

- Astronomical timer based controllers will be used for automatic dusk to dawn operation of streetlights.
- Integration of automated system to operate electrical equipment as per load requirement to save energy
- To reduce the embodied energy, it is proposed to use energy efficient construction material such as Fly ash bricks & PPC (Fly ash based cement)

During presentation as per Google image based on coordinates provided by PP it was observed that Rau – Pithampur road is passing at a distance of 11.0 meters in the North side and the railway track is passing 43.0m from the south side of the proposed project. The Ralamanadal sanctuary is 18.90 KMs from the site. Committee after presentation and deliberation PP was asked to submit following information for further consideration of the project.

1. Clarification of number of floor in the proposed project.
2. Solid waste generation w.r.t. different types of packing material which has not taken in account, furnished details with their disposal plan.
3. Furnish details of CO₂ carbon emission, quantification of proposed DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print of this activity.
4. Green area & open area details on lay out plan.
5. Worst case scenario w.r.t. if any any spill or leakage occurred then how it what would be handled and their management plan.
6. Back calculation for plantation nos.
7. Proposal of 3000 nos. of seedlings in Green area development plan with numbers and species as suggested during presentation.
8. Revised EMP with inclusion of cost of Additional plantation.
9. Under CER programme allocate appropriate budget through concerned DFO for habitat development in Ralamanadal sanctuary, Indore.

PP vide letter dated 04.05.2022 has submitted the above quer replies and presented before the committee :-

- There are only Ground floor level buildings. Mezzanine will be only at a designated location in one or both corners of buildings, only in case if client required.

Waste Type	Disposal Mechanism
Packaging Waste such as paper, cardboard, plastic, wood, glass, utensils etc.,	Will be sold to MPPCB approved recyclers, vendors.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

E-waste - Discarded computer parts, monitor, keyboards etc., constitutes e-waste and this waste will be stored in an earmarked area	<p>E-waste will be generated after 4-5 years latency period.</p> <p>E-waste will be disposed as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2016.</p>
Hazardous Waste – Used/Waste Oil, discarded oil filters, discarded batteries, discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights etc.,	<p>Hazardous waste will be managed as per the Hazardous Waste (Management & Handling Rules), 2016.</p> <p>Hazardous waste will be disposed to CPCB / MPPCB authorized vendors only.</p>

- No. of trees required as per MoEFCC norms @1tree/80 sqm = $53,774.00/80 = 672$ trees = ~700 trees were calculated for the proposed Warehouse/Logistic Park.
- However, as per the SEAC suggestion during the presentation, 3000 nos. of trees will be planted as a part of greenbelt development through Miyawaki technique for the proposed project. The revised plan along with additional cost has been considered and submitting as a part of this clarification.
- 3000 trees will be planted as a part of greenbelt development for proposed warehouse/logistic park. The greenbelt/landscape will be developed through Miyawaki technique by indigenous/native tree species.
- The seedlings to be planted will be procured from the forest department. The revised capital cost of the greenbelt development will be INR 42.0 Lacs and recurring cost of INR 1.0 Lacs and the same has been incorporated in the EMP cost.
- As informed above, as per the suggestion of the committee 3000 trees will be planted as a part of greenbelt development for proposed warehouse/logistic park through Miyawaki technique and the same has been considered for carbon footprint. Also, it has been suggested by the committee that if plantation of 3000 trees is carried out then it will take care of the carbon sequestration of the carbon footprint from the proposed activity. The same has been committed by us in point no. 6 and the EMP capital and recurring cost have been revised considering the planation of 3000 trees.
- It is to inform you that DG set for the proposed project is planned only for the power back-up.

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Construction for Warehouse/Logistic Park at Village - Bhenslay, Tehsil - Mhow, Dist.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

Indore, and M.P. Plot Area – 53,774 sqm. with Built up area – 32,566. 97 sqm. Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow strictly the ECBC/ECBC-R norms prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power.
- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 01 Diesel power generating set of capacity 125 kVA is proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG set (1x 125 kVA) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

- ii. Warehouse/Logistic Park shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
- iii. Total water requirement in the summer season will be ~98 KLD out of which domestic (fresh (30KLD) + flushing (15KLD) water requirement is 45 KLD and horticulture water requirement is 53 KLD. Fresh water demand will be ~30 KLD. Wastewater Generation will be ~39 KLD.
- iv. No Wastewater will be discharge in the Sewer outside warehouse/logistic park premises. Surplus treated effluent during rainy season (if any) will be given to the nearby farmers/construction sites as a part of their daily water requirement.
- v. Recycled water system shall utilize this treated sullage and serve for non-contact uses such as flushing and horticulture.
- vi. No Wastewater will be discharge in the Sewer outside warehouse/logistic park premises. Surplus treated effluent during rainy season (if any) will be given to the nearby farmers/construction sites as a part of their daily water requirement.
- vii. Dual plumbing system that utilizes separate piping systems for freshwater and recycled sullage will be adopted for the project.
- viii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.
- ix. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- x. At least 11% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- xi. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- xii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- xiii. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- xiv. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xv. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xvi. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse.
- xvii. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xviii. For rainwater harvesting, 08 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 1251.73 m³/hr. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xix. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xx. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xxi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xxii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xxiii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring report.
- xxiv. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity - 50 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xxv. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 50 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- xxvi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxvii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxviii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
- vii. PP shall be explored the possibility of laying of solar panels on warehouse roofs to generate the green energy for their in –houses uses, their e- vehicles etc.

VI. Waste Management

- i. During the operation phase, solid waste generated from the project shall be ~309 kg per day .
- ii. These all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- vi. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. Total 3000 trees shall be planted in the area of 17745.5 m² (33 % of total plot area) which is developed as greenbelt development.
- ii. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.
- vi. The surplus soil shall be used for plantation purposes.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- c. Proper design of entry and exit points
- d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. Total 592 nos. of proposed Parking's arrangement as in which 319 for Car + 250 for 2-Wheeler + 23 for Truck= 592 nos.
- iv. For smooth movement of traffic internal roads of 9.0 m and 6.0 m (peripheral) are proposed.
- iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP& Corporation Environment Responsibility

- i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 113.0 Lakhs as capital and Rs. 08.7 Lakhs as recurring cost for this project.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

- ii. For this project PP has proposed Rs 05.00 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for habitat development in in Ralamanadal sanctuary, Indore, which shall be implemented within one year.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

7. Case No 9087/2022 Shri Nisar Khan Ajia ka Pat Mohana Dist. Gwalior, MP - 475330 Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry in an area of 1.0 ha. (5000 cum per annum) (Khasra No. 163), Village - Dabka, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP)

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 163), Village - Dabka, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 10296 दिनांक 03/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में एक वृहद तालाब तथा पूर्व दिशा में 480 मीटर पर मानव बसाहट है। इसी प्रकार दक्षिण में 14 मीटर पर तथा पूर्व 470 मीटर पर कच्चा रोड़ स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज के अंदर एक संरचना दिख रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक पुराना वाच टॉवर है। समिति ने सुझाव दिया कि यह पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संरचना दिखती है, अतः इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं किया जावे तथा परियोजना प्रस्तावक इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन घोषित करते हुए पुनरीक्षित मेप प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण प्लैंग स्टोन माईनिंग का है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज के अंदर एक संरचना दिख रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक पुराना वाच टॉवर है। समिति ने सुझाव दिया कि यह पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संरचना दिखती है, अतः इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं किया जावे तथा परियोजना प्रस्तावक इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग जोन घोषित करते हुए पुनरीक्षित मेप प्रस्तुत करें
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन- 5000 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 06.83 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.79 प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख :-

आगामी 05 वर्ष तक	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम डबका के आंगवाड़ी केंद्र की मरम्मत तथा पुताई का कार्य करवाया जाएगा।		20,000/-
योग		20,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, सफेद कैस्टर, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	570
2	परिवहन मार्ग में (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	250
3	प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	चिरोल, नीम, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कचनार, कदम्ब करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	280
4.	ग्राम डबका के विद्यालय परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	चिरोल, नीम, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कचनार, कदम्ब, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
		कुल वृक्षारोपण	1200

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

8. Case No 9088/2022 M/s Raj Real Estate Developers, Prop., Shri Rajeev Kumar Gupta, Dharamshala Road, In Front of Ganesh Bhojnalaya, Dist. Shivpuri, MP, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 3.20 ha. (38000 cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Khiriya Sunwai, Tehsil - Narwar, Dist. Shivpuri (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Khiriya Sunwai, Tehsil - Narwar, Dist. Shivpuri (MP) 3.20 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 518 दिनांक 10/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान पार्वती नदी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति यह पाया कि गूगल इमेज के अनुसार खनन क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान स्थिति में खनन क्षेत्र का कोई भी भाग पानी में नहीं डूबा है तथा रेत निकाली जा सकती है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस संदर्भ में उनके द्वारा खनन अधिकारी से मौका मुआयना निरीक्षण करवाकर एक प्रतिवेदन प्राप्त किया है। समिति ने पाया कि खनन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 720 दिनांक 01/04/22 के माध्यम से सूचित किया है कि वर्तमान में स्वीकृत खदान एरिया में पर्याप्त रेत का भंडार है तथा मौका मुआयना के फोटोग्राफ भी संलग्न किया है। समिति ने फोटोग्राम के अवलोकन से पाया कि खदान क्षेत्र में रेत उपलब्ध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर नवीन डी.एस.आर. सत्र 2022-23 उनके द्वारा अपलोड की गई है। इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया गया है जिसमें रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टों की सूची में यह खदान दर्शित है। अनुमोदित खनन योजना के चेप्टर-12 "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/22 में चर्चा हेतु रखा गया था तथा समिति की अनुशंसायें सिया को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई है। नवीन डी.एस.आर. सत्र

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

2022-23 के अनुसार इस खदान की एस्टीमेटेड कैपेसिटी 15000 घनमीटर दी गई है । अतः पर्यावरणी अभिव्यक्ति हेतु 15000 घनमीटर की क्षमता पर ही विचार किया जाना उचित होगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना ।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 15,000 घनमीटर प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.19 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख :-

स. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
खिरिया सुनवाई ग्राम आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण ।	1,00,000
खिरिया सुनवाई ग्राम में वर्ष में 02 बार चिकित्सा शिविर	50,000
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

S. No.	Proposed Plantation Site	Plant Species	Quantity (Numbers)
1	नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की ओर)	वेटीवर/खस (छः - छः इंच की दूरी पर) , नागरमोथा (एक मीटर की दूरी पर) एवं	1500

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

		अन्य स्थानीय प्रजातियां।	
2	नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर)	कटंग बांस, जामुन , अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	1500
3	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, महुआ, आम, पीपल, ईमली, जामुन, बेहड़ा अचार व पलाश आदि ।	500
4	खिरिया सुनवाई के ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, इमली, आवला, सीताफल, कटहल, मुनगा एवं नींबू।	500
Total			4000

9. Case No 9089/2022 M/s Raj Real Estate Developers, Shri Rajeev Kumar Gupta, Prop., Dharamshala Road, In Front of Ganesh Bhojnalaya, Dist. Shivpuri, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (86400 cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Kalyanpur, Tehsil - Karera, Dist. Shivpuri (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Kalyanpur, Tehsil - Karera, Dist. Shivpuri (MP) 4.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 517 दिनांक 10/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

यह रेत खदान सिंध नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है । बैठक के दौरान समिति यह पाया कि गूगल इमेज के अनुसार खनन क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्तमान स्थिति में खनन क्षेत्र का कोई भी भाग पानी में नहीं डूबा है तथा रेत निकाली जा सकती है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस संदर्भ में उनके द्वारा खनन अधिकारी से मौका मुआयना निरीक्षण करवाकर एक प्रतिवेदन प्राप्त किया है । समिति ने पाया कि खनन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 719 दिनांक 01/04/22 के माध्यम से सूचित किया है कि वर्तमान सेटेलाईट इमेज में बादल आ रहे हैं तथा इसके पूर्व की इमेज 2018 की है जिसमें जल भराव दिख रहा है यह वर्षाकाल के पश्चात् की है । वर्षाकाल के पश्चात् नदी का जल धीरे-धीरे कम होने लगता है तथा रेत सतह के ऊपर आ जाती है । वर्तमान में स्वीकृत खदान एरिया में पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है तथा मौका मुआयना के फोटोग्राफ भी संलग्न किया है । समिति ने फोटोग्राम के अवलोकन से पाया कि खदान क्षेत्र में रेत उपलब्ध है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर नवीन डी.एस.आर. सत्र 2022-23 उनके द्वारा अपलोड की गई है । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया गया है जिसमें रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टो की सूची में यह खदान दर्शित है । अनुमोदित खनन योजना के चेप्टर-12 “रिप्लेनिशमेंट प्लान” के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/22 में चर्चा हेतु रखा गया था तथा समिति की अनुशंसायें सिया को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गई हैं। नवीन डी.एस.आर. सत्र 2022-23 के अनुसार इस खदान की एस्टीमेटेड केपेसिटी 45000 घनमीटर दी गई है । अतः पर्यावरणी अभिस्वीकृति हेतु 45000 घनमीटर की क्षमता पर ही विचार किया जाना उचित होगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना ।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 45,000 घनमीटर प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.10.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.47
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.00 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम कल्याणपुर में आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण ।	1,00,000
ग्राम कल्याणपुर में वर्ष में 02 बार चिकित्सा शिविर	50,000
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

S. No.	Proposed Plantation Site	Plant Species	Quantity
1	नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की ओर)	वेटीवर/खस (छः - छः इंच की दूरी पर) , नागरमोथा (एक मीटर की दूरी पर) एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	2300
2	नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर)	कटंग बांस, जामुन , अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	2500
3	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, महुआ, आम, पीपल, ईमली, जामुन, बेहड़ा अचार व पलाश आदि ।	500
4	खिरिया सुनवाई के ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, इमली, आंवला, सीताफल, कटहल, मुनगा एवं नींबू।	500
Total			5800

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

10. Case No 9090/2022 PARMEET SINGH BHATIA, Owner, 22, Nanda Marg, Barwaha, Khargone, MP- 451115 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (8000 Cum/year (Khasra No. 126), Village –Kadwala, Tehsil – Barwaha, Distt. Khargone (M.P.)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1261), Village –Kadwala, Tehsil – Barwaha, Distt. Khargone (M.P.) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 7205 दिनांक 24/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 04.491 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 410 मीटर पर आबादी तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर कच्चा रास्ता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूंकि प्रकरण मुरुम उत्खनन का है, जिसमें ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 8000 मी.3 प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 07.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.64 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख :-

आगमी 05 वर्ष तक	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
-----------------	------------------------------------	--------------

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

ग्राम कदवालिया के प्राथमिक विद्यालय में पुताई का कार्य करवाया जाएगा साथ ही बच्चों के लिए खेल सामग्री तथा बैठने के लिए दरी उपलब्ध करवाई जाएगी ।	20,000/-
योग	20,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	जंगल जलेबी, सिस्सू, चिरोल, नीम, सीताफल, पीपल, सफेद कैस्टर, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	800 पौधे
2	परिवहन मार्ग में (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रजीवा, नीम, सिस्सू, कदम्ब एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया ट्री-गार्ड के साथ	150 पौधे
3	ग्राम कदवालिया के विद्यालय परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	चिरोल, नीम, मोलश्री, पुत्रजीवा, कचनार, कदम्ब, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	200 पौधे
4	ग्राम कदवालिया के मंदिर परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	पुत्रजीवा, कचनार, पीपल, कदम्ब, करंज, मोलश्री, चिरोल, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	50 पौधे
5	ग्राम कदवालिया क्षेत्र में ग्रामवासियों एवं पंचायत से परामर्श लेकर	आवला, संतरा, महुआ, पपिता, कटहल, अमरुद, मूंगा, नाम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	2400 पौधे

11. Case No 9091/2022 NISAR KHAN] HOUSE NO. 87, VILAAGE VIRAWALI, POST IPS COLLEGE RAIPUR, Distt. Gwalior (MP)-475330 Prior Environment Clearance for STONE GITTI in an area of 1.850 ha. (6500 Cum/year (Khasra No. 2599/1/2), Village – Sehore , Tehsil – Narwar, Distt. Shivpuri (M.P.)

This is case of STONE GITTI. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2599/1/2), Village – Sehore , Tehsil – Narwar, Distt. Shivpuri (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 289 दिनांक 24/02/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 04.350 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर-पूर्व दिशा में 375 मीटर पर तालाब तथा पश्चिम दिशा में 500 मीटर पर नहर है । इसी प्रकार में दक्षिण-पूर्व दिशा में 460 मीटर पर तथा दक्षिण दिशा में 435 मीटर पर आबादी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 6500 मी.3 प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. .03.58 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम सिहोर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अलमारी लाइब्रेरी के लिए और एक कंप्यूटर, प्रिंटर टेबल के साथ	60,000
ग्राम सिहोर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 20 छायादार वृक्षों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ) को ट्री गार्ड के साथ लगाना	10000
योग	70,000

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

वर्षवार	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्यामें)
प्रथम वर्ष	तालाब के किनारे एवं मंदिर के चारो तरफ	आंवला, सिस्सू, नीम, पीपल, करंज, खमेर, चिरोल, कचनार, सीताफल, कुम्भी, बीजा, अमलतास, पाकड, दहिमन, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, करंज, खमेर, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
प्रथम वर्ष	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, नीम, पीपल, कचनार, कुम्भी, शीशम, दहिमन, आम, आंवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	300
	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, सीताफल, आंवला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	700
द्वितीय वर्ष	ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र	कदम, नीम, कचनार, अशोका, पुतरनजीवा, मौलश्री, कुम्भी, बीजा, शीशम, दहिमन, पीपल, पाकड, बरगद, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400

- 12. Case No 7245/2020 M/s Tanisha Infracon Pvt. Ltd, B-64, Shaligram Tower, Near Sharon Park, Satellite Road, Ahmedabad, Guj. – 380015 Prior Environment Clearance for approval of Laterite Deposit in an area of 18.33 ha. (81,770 cum per annum) (Khasra No. 1331, 1339, 1340) at Village- Tarnod, Tehsil- Suwasara, District- Mandsaur (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.**

This is case of Laterite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1331, 1339, 1340) at Village- Tarnod,

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

Tehsil- Suwasara, District- Mandasaur (MP) 18.33 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 3144 dated 28/12/2019 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

The case was presented by the PP and their consultant in the 444th SEAC meeting dated 03-07-20, during presentation as per Google image based on coordinates provided by PP, it was observed that the Kachcha road crossing the lease committee recommended that PP shall provide right of access in 7.5m of barrier zone. It is a case of laterite deposit with total area of 18.33 ha., including this mine and according to the latest O.M F.No. L-11011/175/2018/-IA-II (M) dated 12/12/2018 if a cluster or an individual lease exceeds 5 ha the EIA/EMP be made applicable in the process of grant of prior environmental clearance. Therefore committee decided to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

- Commitment from PP that on Kachcha road, right to access shall be provided in 7.5m of barrier zone.
- Environmental Monitoring should be conducted in such a way that from all soil samples heavy metal should be analysed and atleast in one sample analysis of pesticides should conducted.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 444th SEAC dated 03/02/2020 wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA report vide letter dated 06.09.2021 which was forwarded through SEIAA vide letter no. 1863 dated 13.09.2021 and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Amar Singh Yadav from M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P. behalf of PP. During presentation, PP submitted following salient features of the project:-

During presentation it was observed that in the public hearing preceding an issue was raised that a religious place (देव स्थान) exists within lease which may be damaged due to

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

mining activity/operation, blasting will damage the houses, allocated place is Charagah for cattle and approx. 5000 trees are planted on the lease and thus this activity was opposed by the villagers. PP submitted that the religious place is not within their lease area and actually far away from the lease and considering all desired norms lease is sanctioned by Mining Officer. Committee after deliberation decided that clarification of concerned Mining Officer shall be obtained on the issues raised during public hearing for further consideration of this case. During appraisal it was also observed that in the north area trenches are in existence and committee suggested that these trenches can be used for plantation and part of this area shall be left as non mining area on the northern side. After presentation committee asked PP to submit response on following issues including irrelevant/misleading information provided in From-II, such as:

1. M.O. clarification regarding existence of a religious place (देव स्थान) within lease which may be damaged due to mining activity/operation, blasting impact will damage the houses, allocated place is Charagah for cattle and approx. 5000 trees are planted on the lease.
2. Details of activities proposed by the villagers around the देव स्थान.
3. In point no. 10- C “no fund proposed for ESR/ CER .
4. In point no.25- no tree cutting proposed, while during Public Hearing mentioned 5000 trees are existed at village, clarify current status.
5. Justify, why maximum peak value of PM₁₀ & noise level observed at project site.
6. Permission letter of Gram Sabha for water drawl should be submitted.
7. Why deploying of DG set of 200kVA submit waste oil disposal plan.
8. Why pesticide analysis is not carried out as per specific TOR point.

Later on the case was recommended for delisting in the 434th SEAC meeting dated 15/12/21 wherein it is recorded that “PP has not submitted desired information in the stipulated time even after given reminder letter. Hence, these cases are recommended by the committee for delisting in the light of MoEF&CC, O.M. File no. J-11013/5/2009-IA-II (Part), dated 30th October, 2012.

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 20/2/22 के माध्यम से वांछित जानकारी सिया को प्रस्तुत की गई । सिया की 711वीं बैठक दिनांक 08/03/22 को प्रकरण को परियोजना प्रस्तावक से जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण कोरिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया ।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन तथा पर्यावरण सलाहकार श्री अमर यादव उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा प्रभारी खनिज अधिकारी, कार्यालय खनिज शाखा जिला मंदसौर म.प्र. (पत्र क्रमांक 291 दिनांक 11/2/22) से देवस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जिसके उत्तर में उन्होंने सूचित किया कि सर्वे क्रमांक 1339 के उत्तर दिशा में एक हिंदू मंदिर है तथा उस तक जाने का रास्ता इसी खसरे के बीच से होकर निकलता है । प्रभारी खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि खसरा क्रमांक 1339 पर कोई पेड़ नहीं लगे तथा सर्वे क्रमांक 1339 पर जल संवर्धन हेतु एक जल संरचना का निर्माण किया गया है तथा एक 1800 कंटूर बनाये गये हैं । प्रभारी खनिज अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं है एवं खदान के आसपास कोई आवासीय घर नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर उनके द्वारा देवस्थान के चारों ओर खनन क्षेत्र में 100 मीटर का सेट-बैक छोड़ा गया है तथा बैकल्पिक पहुँचमार्ग मंदिर तक प्रस्तावित किया गया है । इसी प्रकार खनिज क्षेत्र में विद्यमान जल संरचना के आसपास भी 1.43 हे. का नॉन माईनिंग जोन छोड़ा गया है । इसी प्रकार खनिज क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में जहाँ से कच्चा रास्ता होकर निकल रहा है उसको भी नॉन माईनिंग जोन घोषित किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल स्वीकृत खनन क्षेत्र 18.33 हेक्टेयर है, अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के पश्चात् भी 81,770 घनमीटर लेटराईट का उत्पादन किया जा सकता है तथा जितने भी नॉन माईनिंग क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उनमें वृक्षारोपण व चारागाह विकास का कार्य किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो नॉन माईनिंग क्षेत्र प्रस्तावित किया जा रहा है (देवस्थान के चारों ओर खनन क्षेत्र में 100 मीटर का सेट-बैक, मंदिर तक बैकल्पिक पहुँचमार्ग हेतु खनन क्षेत्र, खनिज क्षेत्र में विद्यमान जल संरचना के आसपास भी 1.43 हे. का नॉन माईनिंग क्षेत्र तथा दक्षिण क्षेत्र में जहाँ से कच्चा रास्ता होकर निकल रहा है उसको भी नॉन माईनिंग क्षेत्र) उसके कुल क्षेत्रफल की गणना कर प्रोडक्शन प्लॉन के साथ जस्टीफाई कर प्रस्तुत करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र कि नॉन माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चारागाह का विकास किया जावेगा ।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

13. Case No. – 6561/2019 M/s Untra Mines and Minerals, Smt. Pushpa Parmer, Village - Chainpura, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (48,500 cum per annum) (Khasra No. 550, 552, 577), Village - Manpur, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) EIA Consultant In-Situ Enviro Care, Bhopal

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 550, 552, 577), Village - Manpur, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 449वीं दिनांक 24/07/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के दक्षिण-पूर्व दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 325 मीटर पर तालाब तथा दक्षिण दिशा में 500 मीटर पर आबादी है । खदान क्षेत्र के पश्चिम भाग से 02 सरफेस ड्रेन ओरिजनेट हो रहे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र से निकलने वाले वर्षा जल को गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के माध्यम से एकत्रित कर निस्तारित किया जायेगा । इसी प्रकार खदान क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी भाग में 30 मीटर पर जल रोकने की छोटी संरचना दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आसपास की खदानों एवं किसानों द्वारा वर्षाजल रोकने के लिए इस तरह के अस्थाई संरचना बनाई गई है । समिति ने यह पाया कि पूर्व क्षेत्र में बनी इस संरचना में चूँकि पानी भरा रहता है, अतः उत्तर-पूर्वी भाग में 20 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान धूल की समस्या, फसलों पर दुष्प्रभाव, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से संबंधित आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में एड्रेस किया गया है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये तथा कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाये ताकि इन समस्याओं का निवारण हो सके । सामाजिक कल्याण के कार्यों को सी. ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ पूर्व क्षेत्र में बनी जल संरचना के कारण उत्तर-पूर्वी भाग में 20 मीटर का सेट-बैक (नॉन माईनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना ।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन –48,500 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.42 लाख एवं रिक्रिंग 03.50 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.50 लाख :-

प्राथमिक शाला मानपुर व ग्राम पंचायत मानपुर के पास सड़क का विकास और रखरखाव (500 मीटर लम्बी x 3.5 मीटर चौड़ी)	1,00,000.00
प्राथमिक शाला मानपुर में 50 बेंच, २० कुर्सी की व्यवस्था एवं २ ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था।	1,00,000.00
आंगनवाड़ी मानपुर में तीन वर्षों तक पोषण आहार का वितरण।	1,50,000.00
ग्राम मानपुर में 500 लोगो हेतु वर्ष में 2 बार चिकित्सा शिविर का आयोजन।	1,00,000.00
कुल व्यय	4,50,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

S. No.	Proposed Plantation Site	Plant Species	Quantity (Numbers)
1	बैरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	आम, नीम, चिरोल, पीपल, एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	जामुन, करंज, पीपल, पलाश एवं स्थानीय प्रजातियां	1800

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

3	मानपुर स्कूल एवं ग्राम पंचायत मानपुर के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां।	1500
4	मानपुर ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व नीम एवं स्थानीय प्रजातियां	500
Total			4800

14. Case No 8255/2021 Shri Anshul Khare S/o Shri Arun Khare, Indrapuri Colony, ist. Tikamgarh, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (24519 cum per annum) (Khasra No. 236/1), Village - Shrinagar, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) EIA Consultant In-Situ Enviro Care, Bhopal

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 236/1), Village - Shrinagar, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 487वीं दिनांक 05/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाइन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 04/04/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अजय मोहन उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान का पूर्वी, मध्य एवं उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मध्य क्षेत्र में जो खुदा हुआ भाग है, उसे सरफेस मैप में दिखाया गया है, क्योंकि हमको खदान इसी स्थिति में 2018 में स्वीकृत हुई थी । हमको अभी तक भू-प्रवेश नहीं मिला किंतु 2015 से हमारी खदानों के चारों ओर से अवैध उत्खनन का कार्य किया रहा है जो धीरे-धीरे खनन करते हुए हमको आवंटित क्षेत्र में भी खनन कार्य करना चालू कर दिये है । इस संबंध में हमारे द्वारा अवैध

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

उत्खनन बावत् कईबार शिकायतें भी की गई है । खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 375 मीटर पर रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान धूल की समस्या संबंधी आपत्ति प्राप्त हुई थी जिसको ई.एम.पी. में एड्रेस किया गया है एवं सामाजिक कल्याण के कार्यों को सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि इस खदान से धूल की समस्या न हो । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ उन पत्रों की फोटोकापी जो परियोजना प्रस्तावक ने अवैध उत्खनन हेतु लिखे है ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना तथा वचन पत्र कि वृक्षारोपण प्रथम 02 वर्ष पूर्ण कर लिया जावेगा ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 04/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -24,519 मी.³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.24 लाख एवं रिकरिंग 03.05 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.4.50 लाख :-

प्राथमिक शाला श्रीनगर व ग्राम पंचायत श्रीनगर के पास सड़क का विकास और रखरखाव (500 मीटर लम्बी x 3.5 मीटर चौड़ी)	1,00,000.00
प्राथमिक शाला श्रीनगर में 50 बेंच, २० कुर्सी की व्यवस्था एवं २ ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था ।	1,00,000.00
आंगनवाड़ी श्रीनगर में तीन वर्षों तक पोषण आहार का वितरण ।	1,50,000.00

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

ग्राम श्रीनगर में 500 लोगो हेतु वर्ष में 2 बार चिकित्सा शिविर का आयोजन 	1,00,000.00
कुल व्यय	4,50,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

S. No.	Proposed Plantation Site	Plant Species	Quantity (Numbers)
1	बैरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	चिरोल, पीपल, व पलाश एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	जामुन, करंज, पीपल, व पलाश एवं स्थानीय प्रजातियां	1800
3	श्रीनगर स्कूल एवं ग्राम पंचायत श्रीनगर के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां।	1500
4	श्रीनगर ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व नीम एवं स्थानीय प्रजातियां	500
Total			4800

- 15. Case No. – 6713/2019 Shri Swapnil Wycliffe S/o Shri Vinod Wycliffe, New Christian Colony, Dist. Sagar (MP) Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.360 ha. (1,680 cum per annum) (Khasra No. 739/1, 738/1, 738/2, 738/8), Village - Ujnethi, Tehsil – Shahgarh, Dist. Sagar (MP).**

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 31/03/2022 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 418वीं बैठक दिनांक 23/01/2020 को टॉर जारी करने की अनुशंसा सहित

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अप्रैल 2022

एसईआईए को प्रेषित किया गया है, जिसमें ग्राम उजनेठी, तहसील शाहगढ़, जिला सागर के स्थान पर ग्राम उजनेठी तहसील सागर, जिला सागर त्रुटिवश टंकण हो गया है, जबकि सभी संबंधित दस्तावेजों में ग्राम उजनेठी, तहसील शाहगढ़, जिला सागर उल्लेखित है। अतः परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त हेतु शुद्धि पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत टंकित हो गया है। अतः समिति अपनी 418वीं बैठक दिनांक 23/01/2020 में टॉर हेतु अनुशंसित ग्राम उजनेठी तहसील सागर, जिला सागर के स्थान पर ग्राम उजनेठी, तहसील शाहगढ़, जिला सागर पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष शर्तें/अनुशंसा यथावत रहेंगी।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)
c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- The Licensee must use minimum number of poiclains and it should not be more than two in the project site.
 - The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

563वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.